(ग) देश में बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार की विस्तृत कार्य-योजना क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) सामान्य मुख्य स्थिति (यू पी एस) के अनुसार, देश में बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुमान 1 जनवरी, 1994 को 9.0 मिलियन लगाया गया है। इनमें से 4.71 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(ख) 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार, 9.0 मिलियन बेरोजगारों में से 5.48 मिलियन शिक्षित हैं।

(ग) नौवीं योजना के दृष्टिकोण में उत्पादक रोजगार को प्राथमिकता दिए जाने पर विचार किया गया है, जो बेरोजगारी और अल्प रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में श्रम सघन क्षेत्रकों, उप-क्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास की प्रक्रिया में स्वतः सृजित होंगे।

सरकार गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम। शहरी क्षेत्रों में, 1.12.1997 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) चालू है, वह भी गरीबों को लाभजनक रोजगार उपलब्ध कराती है। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय योजना के रूप में प्रधान मंत्री रोजगार योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना पर प्रतिबंध

3343. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी भी नई योजना को शुरू करने पर इस समय प्रतिबंध लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबंध कब से लागू है और इसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 16.1.97 को हुई इसकी बैठक में सर्वसम्मति से यथाअनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्किोण पत्र में यह सहमति हुई थी कि "सिद्धांत रूप में, केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) अंतर राज्यीय प्रकृति की स्कीमों, राष्ट्रीय सुरक्षा पर अतिक्रमण के मामलों, चुनिंदा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जहां प्रचालनात्मक कारणों की वजह से केन्द्रीय समन्वय आवश्यक है, तक सीमित की जानी चाहिएं। इस प्रकार की स्कीमों के अलावा अन्य सभी स्कीमें तदनुरूपी निधियों सहित राज्यों को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिएं।"

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) को राज्यों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को योजना आयोग में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

Additional Plan support to Andhra Pradesh

3344. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the additional plan support for 1998-99 Annual Plan sought by the Andhra Pradesh Government;

(b) whether additional plan of Rs. 750/- crores for the State's Annual Plan for 1995-96 has not yet been released;

(c) if so, the reasons therefore; and

(d) the measures taken to release additional plan support for the 1998-99 annual plan, as requested by the Andhra Pradesh Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) The State Government has yet to submit Annual Plan 1998-99 proposals.

(b) and (c) The State Government's Annual Plan 1995-96 was finalised at Rs. 3157.00 crores. At the time of finalisation there was a resources gap of Rs. 1,000 crores. The State Government mobilised Rs. 250 crores as additional resoruce which left a gap of -Rs. 750.00 crores. Planning Commission had visualised that this gap of Rs. 750.00 crores would be met from the Award of the Tenth Finance Commission. The State Government already received Rs. 846.00 crores as per the Award of the Tenth Finance Commission.

(d) The question does not arise.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक विकास दर

3345. **श्री चीमनभाई हरिभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के सभी वर्षों के दौरान कुल औसत आर्थिक विकास दर प्राप्त कर ली गई है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में औसत आर्थिक विकास दर कितनी-कितनी थी;

(ग) उद्योग और अन्य सेवा क्षेत्रों में उच्च राष्ट्रीय विकास का क्या प्रभाव रहा; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त दोनों क्षेत्रों में राज्य-वार कितनी औसत विकास दर दर्ज की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) 1993-94 से 1996-97 तक चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में प्राप्त की गई वार्षिक विकास दरें आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93—1996-97) के लिए लक्ष्य के रूप में निर्धारित 5.6 प्रतिशत वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर से अधिक रही हैं। उच्च वार्षिक विकास दरों का उद्योग और अन्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ा जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में उद्योग और अन्य सेवाओं का हिस्सा आधार वर्ष (1991-92) के 70 प्रतिशत से बढ़कर आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) में 74 प्रतिशत हो गया। प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में औसत कुल आर्थिक विकास दर तथा उद्योग और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में औसत विकास दर को विवरण में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980-81 की कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) की राज्यवार विकास दर

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं पंचवर्षीय योजना का औसत विकास दर		
		कुल एएसडीपी	उद्योग क्षेत्रक	सेवाएं क्षेत्रक
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.4	3.71	7.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.0	7.24	5.91
3.	असम	2.8	4.94	3.21
4.	बिहार	0.4	—0.07	2.73
5.	गोवा	7.6	7.11	8.83
6.	गुजरात	12.1	17.45	7.35
7.	हरियाणा	4.7	5.78	5.21
8.	हिमाचल प्रदेश	5.3	8.82	4.58
9.	जम्मू और कश्मीर	4.4	5.07	4.93
10.	कर्नाटक	4.7	4.97	5.99
11.	केरल	6.7	6.90	7.94
12.	मध्य प्रदेश	6.1	8.66	4.71